इकाई 11 उत्तर भारत में ब्रिटिश विस्तार

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- बता सकेंगे कि किस प्रकार उत्तर भारत, मुख्य रूप से अवध और पंजाब ब्रिटिश शासन के अधीन आये,
- विभिन्न राज्यों पर कब्जा करने की ब्रिटिश नीति में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कर सकेंगे,
- उत्तर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में सहायक परिस्थितियों पर प्रकाश डाल सकेंगे।

11.1 प्रस्तावना

उत्तर भारत, खासकर अवध राज्य में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना मुगल साम्राज्य और अवध राज्य के अस्तित्व के लिए एक चुनौती थी। यहाँ मुगल या अवध राज्य के शासकों के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुता स्थापित हुई। 1764 में हुए बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी गंभीर युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा। 1856 में अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, अवध राज्य के ब्रिटिश सत्ता में विलय के पहले अंग्रेजों को किसी गंभीर चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा।

11.2 मुगल साम्राज्य का पतन और उत्तर भारत में विभिन्न राज्यों का उदय

जैसा कि आपने पहले की इकाइयों में पढ़ा है, मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के आरंभ में हो चुकी थी और 1739 में हुए नादिरशाह के आक्रमण ने रही सही कसर भी पूरी कर दी।

केंद्रीय सत्ता की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए कई स्वतंत्र और अर्द्धस्वतंत्र राज्य उभर कर सामने आये। इनमें से कुछ राज्य ऐसे थे, जिनमें मुगल साम्राज्य के सूबेदारों ने स्वायत्तता की घोषणा कर दी थी और कुछ राज्य ऐसे थे जहां मुगल सत्ता के खिलाफ बगावत कर दी गयी थी। उत्तर भारत में ऐसे राज्यों में अवध, रोहिल्ला, जाट और सिक्ख उल्लेखनीय हैं। इन राज्यों ने अपने राज्य को मजबूत बनाने और उसका विस्तार करने के लिए कभी आपस में समझौता किया, कभी संघर्ष और कभी ब्रिटिश सत्ता की सहायता ली।

हालाँकि अपने अधीनस्थ राज्यों पर मुगल सत्ता का प्रभाव कम हुआ, पर मुगल सत्ता की संप्रभुता कायम रही। 18वीं शताब्दी के दौरान जिन शक्तियों ने अपनी स्वतंत्रता कायम की, उन्हें राजकीय उपाधियों और अधिकारों की जरूरत पड़ी। इसका कारण, आश्रयी राज्यों के लिए मात्र परम्परागत अधिकार प्राप्त करना नहीं था, बल्कि यह अन्य भौतिक कारणों से भी प्रेरित था। दूसरे मुगल प्रशासन के पास प्रशिक्षित कार्यकारी और वित्तीय पदाधिकारी थे, जो प्रांतीय शासकों के पास उपलब्ध नहीं थे। तीसरा कारण, जो खासकर अवध के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण था, यह था कि आरंभ में स्थानीय शासन मुगल सत्ता के नाम से ही स्थापित किए गये। मुगल साम्राज्य से संबंध विच्छेद की औपचारिक घोषणा से ताल्लुकदार अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए प्रेरित हो सकते थे।

11.3 अवध : सहायक संधि से विलय तक

1757 के प्लासी के युद्ध में प्रभावकारी व्यापारियों और सामंतों की मदद से क्लाइव ने बंगाल के नवाब को परास्त किया और उसके स्थान पर कठपुतली नवाब, मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया। इससे कम्पनी के भाग्य में नाटकीय परिवर्तन आया। बंगाल भारत का एक प्रमुख समृद्ध प्रांत था, इस पर अधिकार जमाने से ब्रिटिश सत्ता को अभूतपूर्व लाभ हुए। इस सिंचित इलाके से अंग्रेजों को भू-राजस्व के रूप में तीन करोड़ रुपये प्राप्त होते थे। इसका उपयोग उन्होंने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के पोषण और अधिक सेना की नियुक्ति और अपने कर्मचारियों की समृद्धि के लिए किया। इसका परिणाम तब सामने आया जब कम्पनी की सेना ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला (अवध के नवाब) और मुगल बादशाह, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हरा दिया। इसके बाद से इस उपमहाद्वीप में कम्पनी सर्वशक्तिमान शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। कम्पनी ने बादशाह से दीवानी हासिल की और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त किया तथा अवध के नवाब को सहायक संधि करने के लिए मजबूर किया। अपने इन कार्यों से कम्पनी ने भारत में अपनी स्थिति को एक बार फिर वैध बना दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र भी निर्मित किया जो उसके अधीनस्थ क्षेत्रों और पश्चिमी भारत के अपेक्षाकृत अशांत इलाकों के बीच "बफर" का कार्य कर सके।

अक्तूबर 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में जिस सेना ने ब्रिटिश फौज के साथ युद्ध किया था उसमें अवध सेना की भूमिका सबसे ज्यादा थी। इसमें मुगल, दुर्रानी और स्थानीय अवध की सेना शामिल थी। इस सेना में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। इसमें ज्यादातर भाड़े के सैनिक थे जो लूटपाट में अधिक रुचि रखते थे। इन्होंने युद्ध के बीच में ही कम्पनी और नवाब के सामानों को लूटना शुरू कर दिया। वस्तुतः यह सेना समग्र रूप में अवध समाज का प्रतिनिधित्व करती थी।

अवध के कुलीन वर्ग में तीन तरह के लोग थे, इनकी परम्परा और संस्कृति एक दूसरे से भिन्न थी —

i) अवध राज्य और इसके बड़े पदाधिकारियों में शिया मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या थी, इनकी जनसंख्या काफी कम थी और ये अपने आपको राजकीय कुलीन वर्ग का सदस्य मानते थे।

ii) मुंशियों की जाति में कायस्थ और खत्री थे, जिनका अवध के प्रशासन में बाहुल्य था।

iii) राजपूत और ब्राह्मण भूमिपति जो अधिकतर जमींदार थे, पर प्रांतीय प्रशासन में उनका कोई दखल नहीं था।

केवल स्थानीय और केंद्रीय शक्ति के बीच ही तनाव नहीं था, बल्कि जमींदारों द्वारा स्वतंत्र होने के प्रयत्नों के कारण भी शासन दुर्बल हुआ। लगभग अस्सी प्रतिशत हिंदू और मुसलमान जमींदारों ने यह दावा किया कि अवध राज्य के संस्थापक सआदत खाँ के आने के पहले से ही वे जमींदार थे। अतः अधिकांश भूमिपति अपने को अवध के प्रांतीय शासकों से पुराना और स्वतंत्र मानते थे।

इस स्थिति में यह आश्चर्यजनक नहीं है कि अवध का सूबेदार नियुक्त होने के बाद सआदत खाँ ने हमेशा मुगल बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया और अपने नये प्रांत का दौरा सैनिक अभियान के रूप में किया ताकि बागियों को दबाया जा सके। इस प्रकार अवध राज्य ने मुगलों के माध्यम से वैधता प्राप्त की और अपनी सत्ता को स्थानीय तौर पर बल प्रदर्शन के सहारे स्थापित किया। 1764 में अंग्रेजों के हाथों हारने और अधीनस्थ होने के बाद और 1819 में मुगल सत्ता से संबंध विच्छेद करने के बाद उनके लिए अपने मातहतों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करना आवश्यक हो गया। यहाँ तक कि 1857 के विद्रोह में जब उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया तब भी उन्हें मुगलों के नाम से ही काम करना पड़ा।

11.4 ईस्ट इंडिया कम्पनी को सहायक संधि से लाभ

हालाँकि अवध में शुजाउद्दौल को पुनः पदस्थापित कर दिया गया, पर एक संधि के माध्यम से वह कम्पनी की शर्तों में जकड़ गया, जिसके तहत उसे आपसी प्रतिरक्षा (जिसका भुगतान नवाब को करना था) अवध क्षेत्र में कम्पनी के लिए कर मुक्त व्यापार की छूट और युद्ध हर्जाने के तौर पर पचास लाख रुपये देने थे। इस संधि का प्रभाव केवल इसमें सम्मिलित सदस्यों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि उत्तर भारत के इतिहास पर भी इसके दूरगामी प्रभाव पड़े।

सहायक संधि के तहत नवाब ने अवध में स्थाई तौर पर ब्रिटिश सेना की मौजूदगी की मंजूरी दे दी और इसके लिए प्रति ब्रिगेड दो लाख दस हजार रुपये देना भी मंजूर किया। उसने अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की भी मंजूरी दी और यह भी वादा किया कि अंग्रेजों की सहमति के बिना वे किसी भी यूरोपीय की नियुक्ति नहीं करेंगे या सहायता नहीं लेंगे। आने वाले वर्षों में रेजिडेंसी की व्यवस्था काफी निर्णायक सिद्ध हुई। राज्य क्षेत्रतीत संरक्षण देकर, पेंशन की सुविधा मुहैय्या करवा कर और सम्मान तथा तरक्की का अवसर देकर रेजिडेंट ने काफी महत्वपूर्ण लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया और इस प्रकार रेजिडेंट अवध राजधानी में एक नयी शक्ति के रूप में सामने आया।

अवध में राज्य क्षेत्रतीत अधिकारों, मानव शक्ति और अर्थ का जो लाभ अंग्रेजों को मिला उसने भारत का राजनीतिक

नक्शा बदलने में निर्णायक भूमिका अदा की। अवध और बिहार से सैन्य बल की प्राप्ति और बंगाल के लोगों तक अवध के शासकों से धन की प्राप्ति के कारण कम्पनी को मराठों और सिक्खों पर लगातार विजय प्राप्त करने में सहूलियत हुई और इस प्रकार ब्रिटिश भारत में एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभर कर सामने आये। कम्पनी ने अवध राज्य के बागियों को राज्य क्षेत्रतीत संरक्षण प्रदान किया और इस प्रकार अवध पर अंकुश लगाया जा सका तथा साथ ही साथ ऐसे लोगों का एक दल कायम किया जो कम्पनी के प्रति निष्ठावान हों।

कम्पनी ने अवध की राजधानी में पदस्थापित अपने रेजिडेंट के माध्यम से लगातार शासकों की शक्तियों का हनन किया और उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक यह स्थिति आ गयी कि राज्य के अधिकांश पदाधिकारी, दरबारी और बड़े भूमिपति कम्पनी के प्रति निष्ठावान हो गये और उसे ही प्रमुख शक्ति मानने लगे। यहां तक कि आसफुद्दौला और सआदत अली खाँ जैसे नवीन परिवार के लोगों ने भी गद्दी प्राप्त करने के लिए कम्पनी का सहारा लिया। इस प्रकार, अपनी कूटनीतिक चालबाजियों और शक्ति प्रदर्शन के बल पर कम्पनी ने इतने ज्यादा अधिकार प्राप्त कर लिए कि 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय स्वाभाविक सा प्रतीत होने लगा।

11.5 कंपनी द्वारा कब्जा और अवध राज्य का प्रतिरोध : 1765-1775

सहायक संधि के तहत अधीनस्थ की स्थिति में आने के बावजूद अवध शासकों ने विभिन्न प्रकार से स्वतंत्र रूप में कार्य करने का प्रयास किया। कम्पनी के विरोध के बावजूद शुजाउद्दौला ने 1 लाख सैनिकों की प्रशिक्षित सेना गठित की थी। उसने 150 के लगभग फ्रेंच पदाधिकारियों की भी सेवा प्राप्त की, जो एक उच्चस्तरीय तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे। इसके अतिरिक्त उसने कम्पनी की सहायता से 1774 में रोहिलखंड और इटावा को अपने कब्जे में ले लिया। उसने प्रतिरोध स्वरूप अवध राज्य में कम्पनी और अन्य यूरोपियों के व्यापार करने पर कुछ बंदिश लगाई। यहां तक कि 1765 में नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई इलाहाबाद की संधि के अनुच्छेद 8 का शुजाउद्दौला ने कसकर विरोध किया, जिसमें अंग्रेज व्यापारियों और उनके दलालों को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का प्रावधान था। पर उसे कम्पनी द्वारा दस्तक प्राप्त व्यापारियों और एजेंटों को व्यापार करने देने की बात माननी पड़ी पर शुजाउद्दौला को जिस बात का डर था, वही हुआ। ये व्यापारी चुंगी मुक्त व्यापार करने के अधिकारी थे पर वे बिक्री कर और पारगमन शुल्क देने से भी इन्कार करने लगे, घरेलू बाजार में हस्तक्षेप करने लगे और इस प्रकार व्यवहार करने लगे मानो वे नवाब के कानून के दायरे से बाहर हों।

नवाब ने इन कार्यकलापों का कसकर विरोध किया। नवाब के विरोध को देखते हुए कम्पनी ने मई 1768 में अपने सभी व्यापारियों और एजेंटों पर प्रतिबंध लगा दिया और अवध तथा बनारस में मुक्त व्यापार करने का प्रावधान वापस ले लिया।

इस व्यापार से अंग्रेज व्यापारियों को इतना ज्यादा लाभ होता था कि कुछ व्यापारी इस प्रतिबंध से खिसिया कर वापस इंग्लैंड चले गये। उन्होंने लंदन में कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स पर प्रतिबंध हटाने के लिए दबाव डाला। उनके दबाव के कारण कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स ने 1771 में यह प्रतिबंध हटा दिया। शुजा ने इसका विरोध किया और संधि तोड़ने की धमकी दी। कोई विकल्प न रहने पर वारेन हेस्टिंग्स ने वायदा किया कि "कोई अंग्रेज उनके राज्य में नहीं रहेगा और मैं कभी भी अंग्रेजी गुमाश्तों और उनके लोगों के बीच हुए मतभेद में टांग नहीं अड़ाऊंगा।"

11.5.1 अवध प्रतिरक्षा का दुर्बल होना : 1775-1801

1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आसफुद्दौला ने अवध का शासन अपने हाथ में लेने की कोशिश की। मुगल परम्परा में प्रांतीय स्तर पर वंशानुगत अधिकार का कोई बना बनाया नियम नहीं था, अतः आसफुद्दौला को गद्दी के अन्य दावेदारों का भी सामना करना पड़ा। इस प्रक्रिया में उसने ईस्ट इंडिया कम्पनी के साथ एक समझौता किया, जिसके कारण उसे नवाबी तो मिल गई, पर राज्य को काफी नुकसान उठाना पड़ा।

अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आसफुद्दौला ने कम्पनी से नई संधि की और इसके तहत उन्हें नई छूटें दीं। उसने अंग्रेजों को बनारस राज्य दे दिया, 50,000 रुपये और अधिक देने का वादा किया, यह रकम पहले निर्धारित रकम की एक तिहाई थी। इस रकम का उपयोग अवध में कम्पनी की सेना के रखरखाव के लिए किया जाता था। उसने राज्य की सेवा में कार्य कर रहे या राज्य में रह रहे सभी यूरोपीयों को निष्कासित करने का वचन दिया, कम्पनी के अनुमोदन पर ही वह किसी यूरोपीय नागरिक को रख सकता था। उसे कम्पनी के साथ अपने संबंधों को मुगल बादशाह से अपने संबंध की अपेक्षा अधिक तरजीह देनी थी। इस प्रकार अपने शासन के आरंभ से ही आसफुद्दौला ने स्वीकार कर लिया कि वह ईस्ट इंडिया कम्पनी पर पूरी तरह निर्भर है।

इस प्रकार अंग्रेजों ने शासकीय वर्ग के आपसी मनमुटाव का फायदा उठाया और अवध में अपनी स्थिति मजबूत की। बहुत जल्द ही कम्पनी की मांग बेहद बढ़ गयी, जिसे पूरा करने में अवध शासक असमर्थ था। अब कम्पनी को खास जमीन पर तनख्वाह अर्थात् भू राजस्व वसूल किए जाने के बाद उसे सीधे कम्पनी के कोष में जमा कर देना था, इस प्रकार अवध राज्य की उसमें कोई भूमिका नहीं होनी थी। इस व्यवस्था से कम्पनी का अवध प्रशासन पर प्रभाव जबरदस्त

हो गया। कम्पनी ने अपने मनचाहे जिलों का चुनाव किया, इन जिलों में अपने मनमुताबिक राजस्व अधिकारियों की बहाली की, उनके कार्यकलापों और खाताबही को नजरअंदाज किया और कम्पनी की सेना का उपयोग कर अपनी मांगों को जबरदस्ती पूरा किया। 1797 में आसफुद्दौला की मौत के बाद राज्य के मामलों में कम्पनी का दखल और भी बढ़ गया। अपनी कम्पनी विरोधी विचारधारा के कारण आसफुद्दौला का पुत्र और उत्तराधिकारी वजीर अली कम्पनी की दृष्टि में सही उम्मीदवार नहीं था। जनवरी 1798 में कम्पनी और कुछ दरबारियों की सहायता से उसे पदच्युतकर दिया गया। इसके बाद सआदत अली खाँ को गद्दी पर बैठाया गया। इस प्रकार सआदत अली खाँ आसफुद्दौला के बाद ऐसा दूसरा नवाब था, जिसने गद्दी हासिल करने के लिए कम्पनी की सहायता ली। पर वह कम्पनी पर और भी ज्यादा निर्भर था। आरंभ में उसने कम्पनी को काफी बड़ा क्षेत्र देने का वादा किया पर बाद में कम्पनी ने भूमि के बदले नकद राशि को प्रमुखता दी। अवध में रह रही अंग्रेजी सेना के रखरखाव के लिए निर्धारित राशि में 20 लाख रुपये की बढ़ोतरी कर दी गयी और अब नवाब को हर साल कम से कम 76 लाख रुपये कम्पनी को देने थे। इसके अतिरिक्त अपने भतीजे के स्थान पर गद्दी हासिल करने के एवज में उसे कम्पनी को बारह लाख रुपये देने पड़े। अंत में, नवाब ने यह भी स्वीकार किया कि "नवाब सआदत अली खाँ किसी भी विदेशी शक्ति से बातचीत के लिए कम्पनी की अनुमति लेगा और उनकी जानकारी के बगैर कोई भी बातचीत नहीं होगी।" इस प्रकार अवध के शासक को वित्तीय तौर पर कमजोर बनाने के साथ-साथ कूटनीति के स्तर पर भी पंगु बना दिया गया।

11.5.2 1801 की संधि

नया गर्वनर जनरल लार्ड वेलेज़ली इस संधि से संतुष्ट नहीं हुआ और 1801 में नयी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए नवाब को मजबूर किया। इस संधि के तहत उसे दोआव, गोरखपुर और रोहिलखंड के इलाके कम्पनी को दे देने थे।

नवाब के राज्य क्षेत्र को संकुचित करने के साथ इस संधि में तीन महत्वपूर्ण पहलू थे, जिन्होंने अवध राज्य को अंतिम तौर पर निष्क्रिय बना दिया :

i) अवध की सेना की संख्या घटाकर एक दहाई कर दी गयी।

ii) कम्पनी ने सभी विदेशी और घरेलू शत्रुओं से अवध की रक्षा करने का भार अपने ऊपर ले लिया।

iii) अवध के शासक को अपने सुरक्षित क्षेत्र में प्रशासक का काम अपने पदाधिकारियों से सम्पन्न कराना था, जिनका कर्तव्य अपने मातहतों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना था, इस प्रशासन को चलाने में तथाकथित सम्मानीय कम्पनी के पदाधिकारियों की काउंसिल के परामर्श पर काम करने की सलाह महामहिम ने दी।

यह तीसरा प्रावधान कई प्रकार की व्याख्याओं की मांग करता है और यह 1856 में अवध के विलय की पूर्वपीठिका था।

11.5.3 अवध राज्य की अवनति और पतन : 1801-1856

अवध के शासकों से राज्य क्षेत्र हासिल करने के साथ-साथ कम्पनी ने अवध में सफलतापूर्वक एक नये शक्ति केंद्र का निर्माण किया। राज्य क्षेत्रतीत संरक्षण के अधिकार के माध्यम से रेजिडेंटों ने नीचे से ऊपर तक ऐसे लोगों का दल बनाया जो कम्पनी के प्रति निष्ठावान हों। इसके सबसे निचले स्तर पर अवध के वे सिपाही थे, जो कम्पनी की सेवा में शामिल थे या पदभार से मुक्त हो चुके थे। इसके ऊपर वे ताल्लुकदार थे, जिन्हें अवध के नवाब ने हटा दिया था और जिन्होंने कम्पनी से अपील करके अपनी जमीन वापस ले ली थी। सबसे ऊपर के स्तर में राजकीय घराने के वे लोग थे जो अपदस्थ या गद्दी के असफल दावेदारों के संबंधी थे और जिन्हें कम्पनी ने संरक्षण प्रदान कर रखा था। ब्रिटिश वैधता इस हद तक स्थापित हो गई थी कि उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में आसफुद्दौला की माँ, बहू बेगम जैसी राजपरिवार की सदस्या ने अपनी वसीयत में लिखा कि उसके मरने के बाद मस्जिद, आश्रितों और कर्बला के पवित्र स्थल के लिए कुछ राशि छोड़कर सारी राशि कम्पनी के नाम कर दी जाए। जब नवाब सआदत अली ने संरक्षण के इस दुरुपयोग का विरोध किया तो रेजिडेंट ने घोषणा की कि "मेरे विचार में, महामहिम का इस मामले में कुछ भी बोलना बिल्कुल अस्वीकार्य है"।

इस प्रकार अवध में एक वैकल्पिक और सर्वोच्च स्थिति बहाल कर कम्पनी ने अपनी स्थिति मजबूत की और अवध के शासकों की वैधता को नजरअंदाज कर दिया। इसके साथ-साथ कम्पनी ने विभिन्न क्षेत्रीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिये उकसाया और इस प्रकार मुगल साम्राज्य द्वारा प्राप्त अवध राज्य के अधिकार को भी चुनौती दी। इस प्रकार उन्होंने प्रकारान्तर से मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को भी चुनौती दी।

हालांकि अवध वास्तविक रूप में कम्पनी पर पूर्णतः निर्भर हो गया था, पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कम्पनी यह चाहती थी कि अवध के नवाब मुगल शासक से स्वतंत्र होने की घोषणा कर दें। कम्पनी के अधिकारियों ने गाजीउद्दीन को स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसने 1819 में मुगल बादशाह से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर नवाब ने एक नई परम्परा की शुरुआत की। अनजाने में उसने अखिल भारतीय शक्ति के रूप में और मुगल साम्राज्य के विकल्प के रूप में उभरने के लिए अंग्रेजों का रास्ता साफ कर दिया। इसके बाद कम्पनी ने नवाब बादशाह को अपमानित करना और नीचा दिखाना शुरू किया ताकि वे अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। अब अवध के शासक नाम मात्र के लिए ही शासक रह गये थे और उनके राजकीय मामलों में ब्रिटिश अधिकारी मनमाने हस्तक्षेप करते थे। गाजीउद्दीन ने पादशाहे (विश्वास के लिए लड़ने वालों का

बादशाह) और शाह-जमान (युग का शासक) की पदवी धारण का जबकि उसके उत्तराधिकारी नासिरूद्दीन हैदर को कम्पनी ने अपनी पदवी को सीमाबद्ध करने के लिए मजबूर किया और उसे पादशाहे-अवध (अवध का बादशाह) और शाहे-जहान (विश्व का शासक) की उपाधि रखनी पड़ी, बाद वाली उपाधि पर अंग्रेजों ने आपत्ति की और इस उपाधि का प्रयोग केवल घरेलू कार्यों में करने की अनुमति दी गई। इस प्रकार कंपनी ने अवध के शासकों के भौतिक और नैतिक अधिकारों पर इस हद तक अंकुश लगा दिया कि 1856 में उसका विलय स्वाभाविक परिणति प्रतीत हुई। जैसा कि हमने पहले भी अध्ययन किया है (देखिए 11.5) रेजीडेंट ने अवध का प्रशासन मुख्य सचिव के रूप में संभाल लिया।

बोध प्रश्न 1

1) अवध प्रशासन की कमजोरी के क्या कारण थे? 10 पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

2) अवध के अधिकांश भूमिपतियों ने

क) अवध राज्य की एकता के लिए काम किया

ख) अवध के स्थायित्व में योगदान दिया

ग) कम्पनी की सेना को परास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की

घ) अपने को अवध शासक से भी पुराना समझा और अवध के प्रांतीय शासकों से स्वतंत्र रूप में कार्य किया।

3) ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अवध के नवाब पर सहायक संधि क्यों थोपी ? 10 पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

11.6 उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में विस्तार

शुजाउद्दौला द्वारा इटावा और रोहिलखंड पर कब्जा करने और 1801 में कम्पनी द्वारा रोहिलखंड हासिल किए जानें के बाद उत्तर भारत में अवध को छोड़कर पंजाब ही एकमात्र बड़ी शक्ति शेष रह गयी थी।

जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में एक प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता आ गयी और सरकार में लगातार कई बदलाव हुए। एक के बाद खड़क सिंह, नव निहाल सिंह, चांद कौर, शेरसिंह और अंत में

दलीप सिंह गद्दी पर बैठे। षडयंत्र और धोखाधड़ी का बोलबाला था और इन परिवर्तनों में सेना ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसी व्यक्ति को अपदस्थ करने और दूसरे व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाने के दौरान खून की नदियाँ बह जाती थीं।

11.6.1 पंजाब पर अंग्रेजों की निगाह

1830 के दशक से ही अंग्रेज पंजाब पर अपनी निगाहें टिकाने लगे थे। एक बार ब्रिटिश सेना के सेनाध्यक्ष सर हनरी फेन को रणजीत सिंह के पोते की शादी में शामिल होने का न्यौता मिला। उसने इस मौके का लाभ उठाया और यह आंकने की कोशिश की कि पंजाबी सेना को हराने के लिए कितनी सेना की आवश्यकता होगी। इसके बाद गवर्नर जनरल एलेन बौरो ने अक्तूबर 1843 में घरेलू सरकार से पंजाब पर सेना के बल पर अधिकार करने की संभावना पर विचार किया। पर अफगानिस्तान के पंचवर्षीय युद्ध के कारण भारत में ब्रिटिश सेना की स्थिति कमजोर हो गयी थी, अतः पंजाब पर आक्रमण करने का प्रस्ताव उस समय के लिए स्थगित कर दिया गया।

11.6.2 पंजाब पर कब्जा करने का तरीका

अंग्रेजों को जल्द ही सुनहरा अवसर मिल गया। पंजाब में सरकार के लगातार बदलाव, पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार, सेना की अनुशासनहीनता, व्यापारी वर्ग और लाहौर की जनता की उदासीनता आदि ने शासक और शासित के मनोबल को गिराया। पर इसके बावजूद पंजाब सरकार के शीर्षस्थ लोगों, जैसे प्रधानमंत्री राजा लाल सिंह, सेनाध्यक्ष मिसर तेज सिंह, लाहौर दरबार के प्रमुख सरदार डोगरा राजा गुलाब सिंह आदि के बीच मतैक्य था।

सेना और सरकार के ऊपरी तबके पर स्थापित यह एकता प्रथम आंग्ल-पंजाब युद्ध में निर्णायक सिद्ध हुई। यह युद्ध 13 दिसंबर 1845 को हुआ। इस युद्ध में कम्पनी की सेना लगभग ध्वस्त कर दी गयी थी, पर लाल सिंह की अकर्मण्यता के कारण उसे पूर्णतः नष्ट न किया जा सका। कनिंघम ने एक जगह लिखा है कि लाल सिंह के कारण सिक्ख सेना एक नाजुक मौके पर चूक गयी। वह लिखता है कि "जब अंग्रेजों का गोला बारूद समाप्त हो चुका था, जब इनकी सेनाएँ फिरोजपुर की ओर लौट रही थीं और जब किसी भी प्रयास से हार को नहीं रोका जा सकता था, तब सिक्ख अपना दबाव कायम रखने में असफल रहे"। नेतृत्व की इस कमी के कारण पंजाब की मजबूत सेना को लगातार हार का सामना करना पड़ा और उसे 8 मार्च 1846 को लाहौर की अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी। ब्रिटिश सत्ता ने जालंधर दोआब को अपने राज्य में मिला लिया और पचास लाख रुपये के एवज में जम्मू और कश्मीर का इलाका राजा गुलाब सिंह को दे दिया। पंजाब की सेना की शक्ति को कम कर दिया गया। अब इसमें 20 हजार पैदल सैनिक और बारह हजार घुड़सवार रह गये और एक मजबूत ब्रिटिश सेना ने लाहौर में अपना अड्डा जमा लिया। 16 दिसम्बर 1846 को एक नयी संधि पर हस्ताक्षर किये गये, जिसके मुताबिक ब्रिटिश रेजिडेंट (रिजेंसी काउंसिल के मार्फत) को राज्य के हर विभाग के हरेक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया। ब्रिटिश सेना पंजाब में जम गई और उसके खर्चे का भार लाहौर सरकार को उठाना पड़ा।

पर ब्रिटिश इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। उनका अंतिम उद्देश्य पंजाब पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना था। अतः, जब मुल्तान के दीवान ने 1848 में लाहौर दरबार के खिलाफ बगावत की तो बगावत की इस आग को अंग्रेजों ने हवा दी। यह ध्यान रखना चाहिए कि मुल्तान के नवाब को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था। इस आग को फैलाने में अन्य दीवानों ने भी सहयोग किया और खुद भी बगावत की। गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी ने अपनी गृह सरकार को लिखा "राजा शेर सिंह का ससैन्य विद्रोह, दरबार के सैनिकों का सहारा लेकर हुई सरदार छत्तर सिंह की बगावत से राज्य की सेना और सिख जनता संकट की स्थिति में फंस गयी है, मुझे इस स्थिति का ही इंतजार था, अब हम सिख राष्ट्र और पंजाब राज्य के किनारे खड़े होकर युद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि सम्मुख आकर युद्ध कर रहे हैं"।

1849 में सिक्ख सेना बुरी तरह पराजित हुई और पंजाब को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता ने जिस राज्य की रक्षा का वचन दिया था, उसे ही निगल गये।

बोध प्रश्न 2

1) तनख्वाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

....

....

....

....

....

2) किन तरीकों से ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अवध पर राजनीतिक नियंत्रण कायम किया?

....

....

....

....

....

3) पंजाब के अंग्रेजी राज्य के विलय में सहायक प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए।

....

....

....

....

....

11.7 सारांश

इस इकाई में हमने उत्तर भारत की दो प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों अवध और पंजाब के अंग्रेजी राज्य में विलय के कारणों पर प्रकाश डाला और इस बात की चर्चा की कि क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इन्हें हड़प लिया हालांकि अवध के शासक ब्रिटिश दबाव के आगे आसानी से झुक गये, लेकिन 1856 में जब अवध राज्य का विलय किया गया, तो जनता शांत नहीं रह सकी और उनका आक्रोश 1857 के विद्रोह के रूप में व्यक्त हुआ। कम्पनी के हस्तक्षेप से पूरे प्रांत में एक प्रकार का उलट पुलट हो गया, और विलय से अवध के लोगों की भावना को एक धक्का लगा। अवध के भूमिपति, किसान और सिपाही कम्पनी के शासन के विरोधी हो गये।

11.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) देखिए उपभाग 11.3
2) घ
3) देखिए भाग 11.4

बोध प्रश्न 2

1) देखिए उपभाग 11.5.1
2) देखिए भाग 11.5 इसके अंतर्गत शक्ति, कूटनीति की भूमिका और वैधता के निर्माण पर प्रकाश डालना होगा।
3) देखिए उपभाग 11.6.2